कृषि पर आधारित उद्योगों हेतु 1990-91 के लिए रखी गई धनराशि

2559. **श्री रामनरेश यादव :** क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1990-91 के दौरान कृषि पर आधारित उद्योगों के लिए सरकार द्वारा कितनी धनराशि का प्रावधान किया गया है और उसके परिणामस्वरूप कितने लोगों को इन उद्योगों में रोजगार मिल सकेगा ;

(ख) क्या सरकार ने इन उद्योगों के विस्तार तथा उन्नयन के लिए कोई नीति तैयार की है; और

(ग) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

उद्योग मंत्रालय में लघु उद्योग एवं कृषि और ग्रामीण उद्योग विभाग में राज्य मंत्री (श्री श्रीकांत जेना) : (क) से (ग) चूंकि कृषि पर आधारित उद्योगों के विकास में भिन्न-भिन्न अवस्थाओं पर कई एजेंसियां/मंत्रालय और सभी राज्य संलग्न हैं इसलिए यह बता पाना शायद व्यावहारिक नहीं होगा कि सरकार द्वारा 1990-91 के दौरान कुल कितनी धनराशि खर्च की जाएगी और कितने लोगों के लिए रोजगार के अवसर सृजित होंगे। किन्तु खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के लिए 1990-91 के वास्ते 32 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है जबकि 1989-90 में 20.91 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया था। "लघु उद्योग तथा कृषि पर आधारित उद्योगों के संवर्धन तथा औद्योगिक स्वीकृतियों की प्रक्रिया में परिवर्तन करने सम्बन्धी नीतिगत उपायों" के बारे में एक विवरण 31.5.1990 को राज्य सभा पटल पर रखा गया था। नीति सम्बन्धी इस प्रलेख में यह प्रावधान है कि कृषि प्रसंस्करण उद्योग को वित्तीय संस्थानों से ऋण दिलाने के काम में सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाएगी ।

मध्य प्रदेश में औद्योगिक विकास की दर

2260. **श्री अजीत जोगी :** क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान मध्य प्रदेश में औद्योगिक विकास की दर क्या रही है और राष्ट्रीय औद्योगिक विकास दर की तुलना में इसकी स्थिति क्या है;

(ख) मध्य प्रदेश के आदिवासी तथा पिछड़े जिलों में औद्योगिक विकास की दर क्या रही है; और

(ग) इस सम्बन्ध में आठवीं पंचवर्षीय योजना के लिए क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया है ?

उद्योग मंत्री (श्री अजीत सिंह) : (क) केन्द्रीय सांख्यिकीय संगठन से प्राप्त स्थिर मूल्यों पर कुल मूल्य वर्धित सूचकांक के अनुसार मध्य प्रदेश राज्य और समग्र भारत के लिए खनन और उत्खनन, बिजली तथा विनिर्माणकारी (पंजीकृत और गैर-पंजीकृत) क्षेत्रों में 1985-86 से 1988-89 की अवधि के दौरान औसत विकास दर नीचे दी गई है:-

क्षेत्र	औसत विकास दर	
	मध्य प्रदेश	समग्र भारत
खनन और उत्खनन	8.0	3.8
विनिर्माणकारी	11.0	7.4
बिजली	7.5	8.9

(ख) इस प्रकार की सूचना संकलित नहीं की जाती है।

(ग) योजना आयोग ने अभी तक 8वीं पंचवर्षीय योजना तैयार नहीं की है, अतः 8वीं पंचवर्षीय योजना के लिए औद्योगिक विकास दर का लक्ष्य उपलब्ध नहीं है ।